ASSENT TO BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the Copra Cess Bill, 1979 passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 20th February, 1979.

12.03 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling attention, Dr. Baldev Prakash.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): On a point of order. Mr. Kosygin had detailed talks with our Prime Minister and he left New Delhi two days ago . . . (*Interruptions*). You should direct the Prime Minister to make a statement regarding this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not a point of order.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED MALTREATMENT OF REPRESENTATIVES OF PEOPLE'S UNION OF CIVIL LIBERTIES, SINGHBHUM

DR. BALDEV PRAKASH: (Amritsar): I call the attention of the hon. Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Reported maltreatment to the representatives of the People's Union of Civil Liberties from Delhi visiting Singhbhum district on Wednesday, the 7th March 1979 to enquire into the complaints of violation of human rights of Adivasis of Singhbhum district and widespread resentment among the people."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Sir, a team of the People's Union of Civil Liberties from Delhi comprising of :

(1) Prof. Dilip Swamy. Head of the Department of Business Economics, Delhi University,

(2) Shri Soman Dube, Journalist,

(3) Shri George Mathew, Research Scholar, Jawaharlal Nehru University,

(4) Shri Anjan Ghosh, Lecturer, IIT, Delhi.

(5) Dr. Arvindo Ghosh, K. M. College, and

(6) Shri Ashok Kumar Panda, Advocate, Supreme Court,

visited Baharagora Police Station area on 7-3-1979 to enquire into alleged atrocities committed on agricultural labourers living in the jurisdiction of Baharagora Police Station. There was no advance information about their visit to this area. The team visited village Olda and contacted Shri Karunakar Mahapatra who entertained them to a cup of tea. The members of the team were accompanied by Shri Prasoon Goswamy and Shri Dalip Paul, alleged Naxalite workers of the area.

While the members of the team and the alleged Naxalities were leaving the village, Assistant Sub-Inspector K. B. Rai posted at Naya Basan outpost intercepted them, suspecting them to be Naxalites he demanded that they identify themselves. He appears to have treated them roughly although Prof. Dilip Swamy had disclosed their identity and produced the letter he carried from Shri Tarkunde addressed to the Chief Minister, Bihar. The Assistant Sub-Inspector took them to Naya Basan police camp at about 5.30 p.m. and kept them there until the Circle Inspector of Baharagora arrived with a police party at the Police Camp at about 8 p.m. A crowd had collected by that time and presumably on being told that the party contained Naxalites, attacked it while it was being

[Shri S. D. Patil]

taken in a vehicle to the Baharagora police station. Some members of the party sufferred injuries as a consequence of this attack. The party appers to have been kept in the Police Station till 3.00 A.M. on 8th March. 1979.

The members of the party were arrested on a complaint of trespass lodged by Shri Karunakar Mahapatra at Police Station, Bahargora and released on personal bonds thereafter. This was the same Karunakar Mahapatra whose house the members of the team had visited at village Olda and who had entertained them to a cup of tea.

An offence under section 143/341/323 IPC was registered at police station, Baharagora on a complaint lodged by Prof. Swamy alleging assault and confinement by Assistant Sub-Inspector Rao, police constables and members of the public. 20 persons have been arrested so far in this case.

The members of the team who had received injuries could not be treated at Baharagora Police Station as the local doctor refused to examine them at night. However, they were rendered First Aid by the thana officer and the Circle officer. Injuries were attended to at Government hospital, Jamshedpur, later.

On receipt of information about the incident, S. P. Singhbhum and S.D.O. Jamshedpur visited the place of occurrence to conduct enquiry. Assistant Sub-Inspector Rai has been suspended. Government of Bihar have directed the Commissioner Ranchi and DIG of Police, Chhota Nagpur range to conduct a joint enquiry. Enquiry report is awaited.

डा० बलदेव प्रकाश उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य मंत्री महोदय ने सदन के सामने वक्तव्य दिया है, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं इस वक्तव्य से संतुष्ट हैं? जो स्टेटमेंट आया है उसको पढ़ने से

(VC)

ही पता लग जाता है कि इस में कितनी [illegible] के साथ कितनी बेबुनियाद बातें लिखी हुई हैं। इस में मंत्री जी ने बताया है कि 6 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल वहां गया। वहां श्री करुनाकर महापात्र से उसने कंटैक्ट किया और उसने उस शिष्टमंडल की मेहमाननवाजी की, उसने शिष्ट मंडल को चाय भी पिलायी। फिर उसी महापात्र की कम्प्लेंट पर ही उनको अरेस्ट किया गया। यानी वह स्टेटमेंट इस सदन के सामने आया है। फिर इस में यह कहा गया है कि उनके साथ नक्सलाइटिस थे और जब वे वहां आये तो पुलिस के सब इंस्पैक्टर ने उनको डिटेन कर लिया। उनसे आइडेंटिटी पेपरस मांगे गये। उनके पास पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज के श्री तारकुण्डे साहब का लेटर था जो कि चीफ मिनिस्टर के नाम लिखा हुआ था। वह लेटर देखने के बाद भी क्या कारण थे कि वहां की पुलिस ने उनको हिरासत में रखा?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आठ बजे वहां सर्किल इंस्पेक्टर भी आ गया और उसके आने के बाद उसने सारी चीजें देखी होगी और वह लेटर भी देखा होगा और तीन घंटे उन्हें हिरासत में बैठे हुए भी हो गये थे, फिर क्या कारण था कि सर्किल इंस्पेक्टर ने कोई कार्यवाही नही की और सुबह तीन बजे तक उनको हिरासत में रखे रखा?

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट मे यह भी कहा गया है कि जब जनता को यह पता लगा कि इसमें कुछ नक्सलाइटिस हैं तो लोग वहां इकट्ठे हो गये और उनको मारने लग गये। क्या वहां यह कानून व्यवस्था है? अगर कहीं नक्सलाइटिस है, और उनके होने का आरोप भी ठीक हो तो क्या जनता को इस तरह का व्यवहार करने का हक है? ये नक्सलाइटिस क्या हैं? ये देश में आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न हुए हैं। यह एक समस्या है जिसको हल करना होगा। नक्सलाइटिस कोई डिजीज नही हैं, यह हमारे देश की सोशो-इकोनोमिक कंडीशन का परिणाम हैं। ये कोई देशद्रोही नही हैं कि इनको गोली मार दी जाए। वे नक्सलाइटिस थे इसलिए इनको मार दिया जाए जैसे कि एमर्जेंसी के समय ऐसा हुआ करता था।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, डा० ने उनको देखने से इंकार कर दिया। यह डाक्टर कौन था? यह सरकारी डाक्टर था या प्राइवेट डाक्टर था? अगर वह सरकारी डाक्टर था तो उसने कैसे इंकार किया कि वह रात के समय उनको नही देखेगा? हो सकता है कि उसने कुछ सीरियसली इंजर्ड हों। क्या डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी कि उसने उन्हें देखने से इंकार क्यों किया?

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो वक्तव्य सदन के सामने आया है, इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि यह झूठ का पुलिन्दा हो। जिस तरह से वहां पर स्थिति है, पीछे सुप्रीम कोर्ट के अन्दर यह बात आयी थी कि [illegible] के अन्दर ट्रायल्स वहां बंद हैं और पुलिस के एस०आई०आर० तक [illegible]

नहीं किये हैं। उसी तरह की यह एक चीज है। यह पुलिस राज का नमूना है। इस सारे वक्तव्य में जो गड़बड़ घोटाला है क्या मंत्री महोदय उससे संतुष्ट हैं और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो क्या वह अपने तौर पर एक निष्पक्ष जांच समिति बिठाने के लिए तैयार हैं? पुलिस के अफसरों ने करुणाकर महापात्र से दरख्वास्त लिखाई, लोगों को इकट्ठा कराया, वहां पर उनकी पिटाई की गई, उनको हिरासत में रखा गया, उनको वहां चोटें लगीं कनप्यूजन में, किसी की आंख के नीचे चोट लगी और किसी को लाठी से चोट लगी, क्या इस सब की जांच करवाने के लिए वह तैयार हैं? मैं जानना चाहता हूं कि उन के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है? इन सब बातों को देखते हुए क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई हाई लेवेल, उच्च स्तरीय जांच समिति बिठाई जाए जो वहां पर जा कर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की जांच करे और सारी बैकग्राउंड में जाए और सिविल लिबर्टीज के जो प्रतिनिधि वहां गए थे उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच करे? अगर देश में यही हाल रहा तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि देश में नागरिक स्वतंत्रता कहीं नहीं रह पाएगी। उन पर अत्याचार हो रहे थे और अगर दिल्ली से कोई देखने के लिए गया तो उनको भी इनाम मिला और कहा गया कि आप देखने के लिए आए हैं क्या अत्याचार हो रहे हैं, लो आप भी थोड़ा सा सैम्पल लेते जाइये उसका जो यहां पर अत्याचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई हाई लेवेल जांच बिठाने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार तैयार है जो सारी घटनाओं की जांच करके रिपोर्ट दे और जो दोषी व्यक्ति हैं, पुलिस इंस्पैक्टर और डाक्टर जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्या उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं?

SHRI S. D. PATIL: There are one or two specific points which the hon. Member has raised. There is no question of my subjective satisfaction about the statement itself. The statement is based on the information supplied by the State Government. The question of arrest at the instance of Shri Karunakar Mahapatra may turn out to be something which was a hoax; one cannot say at this stage, because the State Government has already appointed a Committee. As far as action against the police ASI is concerned, he is already under suspension. About the doctor, it appears that he is a local doctor. Government have no information whether he is a private or Government doctor. Because of the pressure that was mounting there, he could not give medical assistance, the local situation developed in such a manner. Suppose he was a Government doctor, at the risk of his life, he should have treated them because these are all responsible, and respectable people. As regards detention from 8.30 to 3 a.m. for nearly 7 hours, only the enquiries will reveal whether this was justified or not and under what circumstances the ASI was compelled to keep them; may be it was in order to give them protection from the fury of the masses; one cannot say.... (*Interruptions*). There was an agitation mainly among the agricultural labour to demand minimum wage. The objective is laudable but it has taken a wrong turn. This has got some relation to the incidents which happened on the 25th November 1978.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा): जो रिपोर्ट मंत्री महोदय ने पढ़ कर सुनाई है उसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि यह अधूरी है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है:

> "The team visited village Olda and contacted Shri Karunakar Mahapatra who entertained them to a cup of tea."

उसके बाद वहां बातचीत होने के बाद:

> "While the members of the team and the alleged Naxalites were leaving the village, Assistant Sub-Inspector K. B. Rai posted at Naya Basan outpost intercepted them, suspecting them to be Naxalites.."

मंत्री जी ने अभी कहा हो सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिये इनको रोका गया हो। लेकिन रपट से स्पष्ट है कि गांव में इनक्वायरी कर के श्री महापात्र ने उनको चाय पिलायी, पूरी बात हुई और जब उस गांव से टीम चल दी तो रास्ते में ए०एस०आई० ने उनको पकड़ कर रौंगफुल कनफ़ाइनमेंट किया। रपट में है कि आदिवासियों पर हो रही ज्यादतियों की जांच के लिये यह लोग गये थे। दो, तीन महीने से वहां का सिचुएशन बहुत ऐक्सप्लोसिव है। 8 नवम्बर, के "आर्यावर्त" अखबार में छपा है कि पुलिस की गोली से एक आदिवासी मरा। इसी अखबार के 18 नवम्बर के संस्करण में छपा है कि पुलिस की गोली से एक मरा और दो घायल हुए। इसी तरह 14 नवम्बर, के "आज" अखबार में निकला है कि डेगाबाद थानान्तर्गत मधवाडीह पंचायत में परसों पुलिस ने आदिवासियों की हिंसक भीड़ पर गोली चलायी। यह घटना अबरक खान के मालिक की जमीन पर धान काटने को ले कर हुई। "आर्यावर्त" के 27 नवम्बर, के संस्करण में छपा है कि

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

पुलिस की गोली से तीन आदिवासियों की मृत्यु हुई। मतलब यह कि वहां पर 2, 3 महीने से भयंकर गोलीकांड हो रहा था, और उसके बाद सिविल लिबर्टीज वालों को खबर गई तो यहां से यह जांच के लिये गये थे। और फिर जांच करने वालों के साथ जो घटना हुई वह आपके सामने है।

आप देखें कि समूचे देश के अखबारों में क्या निकल रहा था, जैसे "हिन्दू" अखबार में है कि :

"Where Violence is a Way of Life. Killing has become routine, murder a legitimised vocabulary of retaliation in Bihar. It is all a question of survival, say those involved in it."

इसी तरह से "टाइम्स आफ़ इंडिया" में है :

"Concern at lawlessnes in Bihar."

"डैकन हैराल्ड" में है :

"Police difficulty in maintaining law and order".

"संडे" अखबार में है :

"The pahalwans, police and the public sector management form a league of criminals which rapes women and steals money."

इस तरह से दो, तीन महीने से यह घटनायें हो रही हैं और लगभग 400, 500 आदिवासी वहां मारे गये हैं। तो जब इतनी पुरानी घटना है और ऐक्सप्लोसिव सिचुएशन है तो क्या गृह मंत्री महोदय वहां गये हैं जांच के लिये ?

दूसरा सवाल यह है कि भारतीय संविधान के मुताबिक केन्द्र में परमानेंट शैडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये कमीशन बना हुआ है। दो, दो गृह राज्य मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई भी आदिवासियों की हालत को देखने के लिये गये ? नहीं तो एक कमीशन है जिस पर हजारों रु० महीने खर्च हो रहा है, क्या शैडयूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को आपने वहां पर भेजा आदिवासियों पर हो रही ज्यादतियों को देखने के लिये ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट है ?

तीसरा सवाल यह है कि ला ऐंड आर्डर और सिविल लिबर्टीज के मामले पर दो महीने पीछे बिहार के राज्यपाल ने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि वहां कोई ला ऐंड आर्डर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि वहां एक मिनिस्ट्री है, उसके बावजूद भी गवर्नर को ला ऐंड आर्डर के लिये मीटिंग बुलानी पड़ी और जब मीटिंग बुलायी तो उन पर चारों तरफ़ से हमला हुआ। अन्त में वह ऊब कर के इस्तीफ़ा द कर के भाग गये। तो एक गवर्नर एक स्टेट में कोई ला ऐंड आर्डर नहीं है उस पर इस्तीफ़ा देता है, इतने भयानक कांड होने के बाद भी क्या गृह मंत्री जी ने बिहार के बारे में वहां के आदिवासियों और हरिजनों पर जो जुल्म हुआ है उसके बारे में कोई कार्यवाही की है कि नहीं ?

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि 8 नवम्बर को फ़ायरिंग हुई, 18 नवम्बर को फ़ायरिंग हुई, हर फ़ायरिंग में, दो, तीन आदिवासी मारे गये हैं। 14 नवम्बर को फ़ायरिंग हुआ है, उसमें भी 3 आदिवासी मारे गये हैं। इस तरह से तो लगातार फायरिंग होता रहा है और दर्जनों आदिवासी पुलिस द्वारा गोली के घाट उतार दिये गये, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जितने आदिवासी 2, 3 महीने में पुलिस द्वारा गोली से मरे हैं उनके बालबच्चों के लिये सरकार ने क्या मुआवजा दिया है और क्या कार्यवाही की है ?

मेरा अंतिम सवाल यह है कि बिहार जल रहा है, कोई ला एंड आर्डर वहां नही है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो इतनी घटनाएं वहां हुई हैं, क्या भारत सरकार इसके लिये तैयार है कि इस सब फायरिंग की जुडिशियल इन्क्वायरी करवा ले ? सिविल लिबर्टीज के लोगों के साथ जो जुल्म किया गया है, किस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया है, इसका टेप-रिकार्ड कर के लाया गया और श्री जयप्रकाश नारायण जी को टेप-रिकार्ड सुनाया गया, जिसे सुनकर उनकी आंख से आंसू गिरने लगे और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई नही हो सकता, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह पूछना चाहता हू कि क्या इन सब जुल्मों की जांच के लिये इस माननीय सदन के सदस्यों की कोई कमेटी बनाने के लिये सरकार तैयार है ?

SHRI S. D. PATIL: The incident on 7-3-79 is not doubt regretted. But all the criticisms that have been levelled by my hon. friend from Bihar are against the State Government. It is for the State Government to take adequate notice of what has been said here . . . .

श्री विनायक प्रसाद यादव : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मोहन लाल पिपिल (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह केन्द्र से संबंधित नहीं है तो मंत्री महोदय बयान क्यों दे रहे हैं ? उनको तो कह देना चाहिये कि राज्य सरकार के पास जाइये।

SHRI S. D. PATIL: I do not want to comment one way or the other. Subsequently, it appears, Mr. Karunakar Mahapatra who entertained a cup

of tea at village Olda to all the six members of the People's Union of Civil Liberties, has also lodged a complaint . . .

श्री मोहन लाल पिपिल : देखिये हम लोगों के साथ घोर अन्याय है, हरिजन और आदिवासियों के साथ यह धोखाधड़ी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please don't get emotional. The hon. Member has put a question, let the Minister reply to that.

SHRI S. D. PATIL: Mr. Karunakar Mahapatra appears to have lodged a complaint against the same persons. It has now come to light that he has also done it in the interest of the landlords. This is the information which I have received. May be, he might have been driven to lodge a complaint against these people.

As far as the paper reports regarding the atrocities committed against Adivasis are concerned, there was already an Unstarred Question on 1-2-79 raised by Mr. A. K. Roy who represents that area on the number of Adivasis killed in police firing in Chhota Nagpur in Bihar during 1978; the names of Alivasis killed; the facts, details and cause of firings. If the hon. Member wants, I can read out the reply. There were five Adivasis killed—three were Maheshwar Janoda, Lupa Munda and Somanath Longa, fourth and fifth were unidentified. The place where the incident took place is Simdega, District Ranchi. I read the reply:

"On 3-8-78, about four thousand Adivasis surrounded Simdega jail, attached the police party and caught hold of the Jailor. The Magistrate on the scene was injured. The mob failed to disperse on warning. Firing was ordered as a result of which one unidentified person was killed."

"(ii) Place—Village chahatu, District Singhbhum, Date—6-11-1978:

An unlawful assembly of about 1,000 armed persons defied prohibitory orders under Section 144 Cr. P. C. and threatened to blow up the bridge over Goelkara-Chaibasa Road. They also threatened to cut down teak wood trees in Santara forest range. Seven leaders were arrested for violating prohibitory orders. The mob became violent and came forward for the rescue of arrested persons. Warnings, followed by lathi-charge proved ineffective. The mob surrounded the police parties resulting in imminent threat of arms being snatched from the police. The lives of the police party wre in imminent danger...'

"(iii) Place—Village Serengda, District Singhbhum. Date. 25-11-1978.

A police patrol party arrested one Shri Shailendra Mahto, who was accused in cases of illegal felling of trees. The arresting party was attacked by about one thousand armed persons, injuring 11 policemen and the accompanying magistrate. Firing was resorted to, to protect the lives of the patrol party. Three persons S/Shri Lupa Munda, Somanath Longa and one unidentified person were killed."

As far as a judicial probe from here is concerned, the Bihar Government is controlled by a Party, there is a regular Government there. The Central Government cannot come in.

As far as appointment of Committee of the House is concerned, again there is the same consideration. So long as there is an inquiry and the report is awaited, it will be too early to consider that proposition.

About reference of this matter to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission, this question can be considered because on an earlier occasion the Prime Minister has also referred certain questions. But it is a matter at what stage it should be referred to them, whether they are willing or not, we have to ascertain; we have to ascertain the willingness on their part whether they will go into

[Shri S. D. Patil]

all these complicated questions or not. After the Inquiry Report is received, we may think about the advisability or otherwise of that.

श्री विनायक प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया है । सिडयूल्ड कास्ट्स कमीशन को तो बीच सरकार से पूछ, जहां से रिपोर्ट मिले, वहां जाना चाहिए । क्या वह वहां गया है या नहीं ?

MR. DEPUTY SPEAKER: He has already replied to that question.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने वहां पर वायलेंस होने के बारे में जो बातें बताई हैं, अगर वे सब बातें ठीक है, तो वायलेंस को तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं — मैं उसको अच्छा नहीं कहूंगा । लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, ऐसा लगता है कि वह एक कुक्ड स्टोरी है । There is a clear connivance, conspiracy, of the police with the landlord and the officials. It is a clear case of conspiracy, according to your own statement. इन लोगों को बैंजीएंस के साथ पीटा गया, और वहां पर जो पाप किये गये थे, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, ताकि आईंदा कोई को एनक्वायरी करने आये ही न । It is an insult to all of us who believe in the rule of law, to the whole House. After all, we fought against authoritarian rule. We fought for the rule of law, and even in our Government we sometimes see that, here and there, there are cases where rule of law is completely violated. I must say that it is a case of borbarous attitude of the Police, and you cannot treat it in a shabby way saying, 'This is the State Government's function; I cannot interfere in that'. Agreed, strictly speaking, according to the Constitution, this is a State subject. But certainly you can advise the State Government. The State Government is our Party Government. Do you think that what happened in Bihar will not affect Delhi and other parts of the country? It will affect.

Therefore, this Government should see to it that the rule of law prevails everywhere in the country and where it has broken down, the Central Government should take action or at least ask the State Government to take action. जो आप ने एनक्वायरी की बात कही, कौन एनक्वायरी करेगा ? डी० आई० जी० साहब करेंगे । जो पुलिस के ही कर्मचारी हैं वह पुलिस के ही खिलाफ एनक्वायरी करेंगे जिन्होंने कि कांसपिरेसी की ।

The accused and the magistrate are the same person. Can you think that it will create confidence in the minds of the public and the poor tribals? May I request the Minister that this inquiry cannot create confidence in the minds of the people there or in the minds of the Members of this House. If you want to do something and not interested in white-washing, then you must ask the Chief Minister to institute an independent inquiry. I do not suggest a judicial inquiry, but, certainly I would like that it should be an independent inquiry, an inquiry independent of the Police. Secondly, it should be a comprehensive inquiry, comprehensive enough to include all the incidents as referred to by my hon friend, which I do not want to repeat. For 2 to 3 months this thing has been going on. Were they Naxalites? If they are what are their demands? I know they want land, they want job in the public sector. They are poor people. They want wages. The economic aspect should also be looked into. I am sorry that aspect cannot be dealt with by the DIG. Therefore, a comprehensive inquiry including this incident, including what happened in the last 2-3 months should be held by a competent and independent authority.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो यह महापात्र साहब हैं, आप ने खुद ही कहा है कि ये लैंड लार्ड्स के साथ में हैं, लैंड लार्ड्स से मिल गए । पहले तो चाय पिला दी इन को फिर एनक्वायरी करा दी । यह बिल्कुल क्लीयर है कि उन का एफ० आई० आर० फाल्स है । तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्यवाही करते ? जो मैजिस्ट्रेट वहां पर थे, एस० डी० एम०, उन के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ? फाल्स कम्पलेंट करना भी जुर्म है । तो जो पुलिस के कहने से यह सब कुछ किया और जिन्होंने पिटाई की पुलिस की मौजूदगी में — These people were in the custody of the Police and they were beaten. I

think that never happens in any civilised society.

एक तरह से लगता यह है, आप अपने बयान में देख लीजिए, ऐसा लगता है कि इनको ले जाया गया और पिटवाया गया । यह जो आप का कहना है कि उन को बचाने के लिये ले जाया गया, नहीं, उन को पिटवाने के लिये वहां इकट्ठा किया और जितने लैंडलार्ड्स थे, जितने पैसे वाले थे, कम्पनी वाले थे, अफसर थे, फारेस्ट के आफिसर्स थे, उन सब ने मिल कर के यह किया । वहां उन की पिटाई अच्छी तरह हुई।

सब से बड़ी दुख की बात यह है कि जयप्रकाश जी जैसे आदमी ने इस पर शोक प्रकट किया है, उन का कहना है कि उन की आंखों में आंसू भी आएं । तो क्या यह सरकार जिस ने देश की दोबारा आजादी के लिये एक मार्डन लड़ाई का नेतृत्व किया वह यह करेगी कि डी०आई०जी० फैसला करेगा । क्या यही कीमत आप के पास है ? मैं नहीं समझता कि पटेल साहब या पाटिल साहब इसके बारे में ऐसा फैसल ऐटीच्यूड लेंगे ? यह मामला गंभीर है । आखिर में सिविल लिबर्टीज यूनियन यहांपर काम करती है, कल को हम लोग भी एन्क्वायरी करने जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, अगर सब के साथ यही हाल हुआ तो क्या होगा ? आप भी मुजफ्फरनगर गए थे । आप तो शायद मंत्री है नहीं कुछ हुआ होगा ? लेकिन अगर कोई एम०पी० गए और उन के साथ भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा ? तो इस तरह के एन्सीडेंट न हों, उस के लिए आप बिहार सरकार को कहिए । मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह से बारबेरस ऐक्शन हुए तो इस देश के लोगों ने बीस महीने जो लड़ाई लड़ी, उसकी कोई कीमत नहीं रह जायेगी ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या आप

(1) Comprehensive enquiry into all the incidents by an independent authority;

Will you recommended this to the Bihar Government? That is No. 1.

दूसरे, जो महापात्र साहब हैं, जिन्होंने पहले चाय पिलाई और फिर झूठी कंप्लेन्ट की, क्या उन के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? और एस० डी० एम० के खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं? इस के अलावा जिन्होंने अटैक किया पुलिस कस्टडी में, वहां जितने पुलिस वाले थे और करने वाले थे, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

तीसरी बात यह है, कि अभी जो प्राब्लम है बेकेंज की, रोटी की, जमीन की, उसको साल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

चौथी बात यह है कि जो लोग मरे हैं उनको क्या आपने कंपेन्सेशन दिया है ? जैसा मैंने पहले कहा है, जो वायलेंस में इंवलव हुये हैं उनके साथ मेरी कोई सिम्पैथी नहीं है

I condemn violence with all my emphasis at my command. I am not snpporting this.

मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इन बातों का जवाब दें । इस मामले को सैंसेशनल ट्रीट न किया जाये । रूल आफ ला , जिस पर जनता पार्टी खड़ी है , उस का वास्तविक सबूत सरकार दे । (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER *rose*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry, only those names which appear in the notice will be allowed. You cannot get up like this. Hon. Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): Sir, I would like to say this that the hon. Member wants that everything should be done according to rule of law. I would certainly say that I am in entire agreement. He must, therefore, realise that this is a State subject. When a Call Attention Notice of this kind has come here, the duty here of the Central Government would be to tell you the facts on the matter that has been brought before us for our attention.

This does not mean that we either approve of it or disapprove of it. You will see that this is a mere narration of the facts. When my hon. colleague replied, he pointed out that this is a report received from the State Government (*Interruptions*). The call attention is with respect to this particular incident and the members of the Civil Liberties' Union's going there and the matter being handled in a particular manner. It is certainly very deplorable. But we shall certainly give the advice and ask the State Government to go deeply into the matter. That is the only thing that can be done at this stage. I am sure, my hon. friend, will appreciate that it is only after a proper enquiry that we can.... (*Interruptions*).

SHRI KANWARLAL GUPTA: How will you take anyone into confidence?

SHRI H. M. PATEL: That is why I said that we shall pass on the views

[Shri H. M. Patel]

that you have expressed here plus what all advice we can give, which, you consider, is called for.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा): अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उस से ऐसा लगता है कि इस घटना की गम्भीरता को वे भी कम करके आंक रहे हैं, हलके ढंग से ले रहे हैं । यह कहना गलत है कि यह सारा का सारा विषय राज्य सरकार से संबंधित है । जहां तक हरिजनों तथा आदिवासियों का प्रश्न है , केन्द्रीय सरकार की विशेष जिम्मेवारी है, यह हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । भारतीय संविधान में इस के लिए स्पेशल प्राविधान है कि आदिवासियों, हरिजनों एवं अन्य वीकर सेक्शन्स की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की है । यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है वह केवल इतना ही नहीं है कि पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज के प्रतिनिधियों के साथ मार-पीट की गई । आप कालिंग अटेंशन को पढ़िये, उस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ।

"आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के हनन की जो शिकायत थी उस की जांच करने के लिए वे लोग गए थे . . .

और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, मार पीट की गई, जिसके कारण एक व्यापक असन्तोष है, "इसमें आदिवासियों की बात स्पष्ट कही गई है, इस लिये केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती ।

अब हमें देखना यह है कि कितनी विषम परिस्थिति है, कितनी लज्जानक स्थिति है । मैं पूछना चाहता हूं उस सिंघभूम जिले में या बिहार के दूसरे जिलों में जहां आदिवासी रहते हैं—कोई सरकार है या नहीं ? वहां अराजकता की स्थिति है, आदिवासी बेचारे मांग करते हैं कि हम को मिनिमम वेज मिले, लेकिन वहां खेती में काम करने वालों को डेढ़ किलो, एक किलो या उससे भी कम अनाज मजदूरी के रूप में दिया जाता है । बिहार सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी कानून में निर्धारित की है—आदिवासी उसी के लिये मांग कर रहे हैं, किसान समिति इस के लिये वहां आन्दोलन चला रही है, लेकिन उन पर गोलियां चलाई जाती हैं । श्रीमन्, इतना ही नहीं, वहां जो पुराने जंगल थे, साल के, महुआ के, तेंदू के, जिन से आदिवासियों का जीवन चलता था, उन को काट कर सैगान के पेड़ लगाये जा रहे हैं, जिस के विरोध में वहां के आदिवासी आवाज उठा रहे हैं । उन का कहना है कि सैगान से हम को क्या मिलने वाला है, महुआ से या तेंदू का फल खा कर हम अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन उन को बरबाद किया जा रहा है । उन की न्यायोचित मांगों को सुनना तो दूर रहा, उल्टा उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं और जो गोलियां बरसाते हैं उन को कुछ नहीं कहा जाता, उन के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं होती । क्या वहां की पुलिस आदिवासियों की हत्या के लिये है ? ऐसी स्थिति में हमारे राज्य और हमारी पुलिस का क्या कर्तव्य है ? ऐसी स्थिति में पुलिस को किस के पक्ष में जाना चाहिये, राज्य शक्ति का उपयोग किस के संरक्षण के लिये होना चाहिये ? क्या राज्य शक्ति का उपयोग उन लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिये जो मिनिमम वेज कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आदिवासियों की जीविका का हनन कर रहे हैं, जो आदिवासियों को मार रहे हैं—मैं इस के बारे में केन्द्र सरकार का स्पष्ट जवाब चाहता हूं ? श्रीमन्, गोलियां केवल पुलिस ने ही नहीं चलाई हैं, नवा बसन गांव के रघुनाथ सिंह जमींदार ने भी गोलियां चलाई हैं और उस की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है । लेकिन न रघुनाथ सिंह को पकड़ा गया और न उस के साथी गुण्डे पकड़े गये । उस ने जमशेदपुर से गुण्डों को बुला कर वहां गोलियां चलाई । ये इतने सम्भ्रान्त लोग—दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड-आफ़-डिपार्टमेन्ट श्री दलीप स्वामी, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं, उन के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल वहां गया था । जस्टिस तारकुण्डे का पत्र लेकर गया था, जो श्री कर्पुरी ठाकुर के नाम था और जिस समय ओलदा गांव से वे लोग निकल रहे थे, के० बी० राय ने पिस्तौल लेकर उन को रोका, दो पुलिस के सिपाही उस के साथ थे । उस ने जस्टिस तारकुण्डे को गाली दी, कर्पूरी ठाकुर को गाली दी, चौधरी चरण सिंह को गाली दी, श्री मोरारजी देसाई को गाली दी । वहां की पुलिस में इन लोगों के लिये कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वे उन को जबरदस्ती पकड़ कर ले गये और उन से कहा—तुम सब को पुलिस की गोलियों से उड़ा देंगे । यह टेप-रिकार्ड उन के पास रखा है, आप उस को सुन सकते हैं, उन को हत्या की धमकी दी गई, रास्ते में उन को पीटा गया और फिर पुलिस कैम्प में ले जा कर पीटा । और फिर चारों तरफ़ से गुण्डों को खबर दे कर बुलवाया गया । यह बात ये गलत कह रहे हैं कि वे अपने आप इकट्ठा हुए । के० बी० राय ने उन तमाम गुण्डों को इकट्ठा करवाया और हमला करवाया । एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट जो थे, वे बाहरगोरा पुलिस स्टेशन से 8 बजे पहुंच जाते हैं । एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट को ये पत्र दिखाते हैं लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है । के० बी० राय झूठी बात कह देता है कि इन के पास बम है, पिस्तौल है । कोई देखता नहीं है कि उन बेचारों के पास सूई तक नहीं है और केवल जस्टिस तारकुन्डे का एक पत्र है । एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट कहता है कि इन को जीप में थाने ले चलो और जब जीप में वे बैठ जाते हैं, तो एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में उन को पीटा गया । प्रो० दलीप स्वामी को लाठी से मारा गया और जो श्री अरविन्द घोस हैं, जोकि एक प्रोफेसर हैं, उन की आंख के नीचे से खून बहने लगा और उन को पुलिस थाने ले आया जाता है और 8 बजे से सवेरे 3 बजे वहां पर उन को रखा जाता है । श्री करुणाकर का गांव ओलदा नहीं है, यह आप का स्टेटमेंट गलत है । मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं—आप ने हाऊस में यह झूठी बात कही है उस का घर ओलदा में है—कि उसका घर गोहरमोहरा में है । इस को आप करेक्ट कीजिए । वह उस गांव का रहने वाला है और उसको बुलाकर इन के सामने झूठी रिपोर्ट लिखाई गई । यह कहा जा चुका है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और वही टेप रिकार्डर में है । इन लोगों के सामने झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई और मुकदमा दर्ज किया गया इन के ऊपर लेकिन प्रो० दलीप स्वामी ने जो रिपोर्ट लिखाई उस का कहीं पता नहीं है । उस रिपोर्ट में,

यह था कि हम को गोली से मारने को कहा और हम को रास्ते में मारा और गुण्डों से पिटवाया गया और हत्या का प्रयास किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि के० वी० राव को केवल सस्पेंड क्यों किया गया। के० वी० राव को, एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट को उन पुलिसवालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह मुकदमा सीधा सीधा है कि यह जो अपराध है, जुल्म है, यह बड़ा भारी अपराध है। उन को केवल आसन से हटा दिया गया। इतनी देर तक उन को बैठा कर रखा गया। 342 का मुकदमा बैठता है। रौंगफुल कनफाइनमेंट, एटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे सीरियस और हीनस आफ़ेन्सेज हैं जोकि उन के खिलाफ़ बनते हैं। उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जब ऐसी बात है, तो डी० आई० जी० की इंक्वायरी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि सही सही तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो मेरे दो, तीन सवाल हैं। यह प्राब्लम सोश्यो और एकोनामिक प्राब्लम है और यह सामाजिक और आर्थिक प्राब्लम है, जिस को जड़ से समाप्त करना चाहिए। वहां जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है, उस का भी इस प्रश्न से सम्बन्ध है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have put questions. Don't go into problems; problems can be discussed separately. This is Calling Attention.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला मेरा प्रश्न यह है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है ? क्या मेम्बर्स आफ़ पार्लियामेंट की एक कमेटी इस काम के लिए नियुक्त की जाएगी जो इस तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई हल निकाले और उस के लिए सुझाव दे और उपाय बताए।

दूसरी बात यह है कि उन लोगों—एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सर्किल इंसपेक्टर, थानेदार, और के० वी० राव और दूसरे गुण्डों को गिरफ्तार क्यों नही किया गया, इसका जवाब आप दें।

तीसरा सवाल हमारा यह है कि इस सब के लिए कोई जूडिशियल इंक्वायरी फाइरिंग की हो, इस के लिए आप क्या करना चाहते हैं और चौथा प्रश्न यह है, जो सब ने पूछा है और जिस का उत्तर अभी तक नही आया है, कि जो लोग गोली से मारे गये, उन मृतकों के आश्रितों को जीवित रखने के लिये कोई सहायता आप देने जा रहे हैं या राज्य सरकार को इस तरह का निदश या सुझाव आप देने जा रहे हैं कि उन को उचित मुआवजा दिया जाए और तत्काल उन लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, इस के लिये आप क्या करने जा रहे हैं।

SHRI H. M. PATEL: I am very sorry that the hon. Member is so much worked up on this issue. Undoubtedly tribal welfare is the responsibility of the Central Government and we will certainly discharge it. But this Calling Attention Notice is with reference to a particular matter. I will read it. It says:—

> "The reported maltreatment to the representatives of the Peoples union of Civil Liberties from Delhi visiting Singhbhum district on Wednesday, the 7th March, 1979 to enquire into the complaints of violation of human rights of Adivasis of Singhbhum district."

We have given the report which was received from the State Government. It has been placed before the nonourable House. All these points which the hon. Member has mentioned will certainly be brought to the notice of the State Government and we will also certainly pursue matters in which we are specially interested.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Sir, on a point of order.

I would like to invite your attention to Article 338 and 339 of the Constitution. It is not sufficient that a reference be made to the State Government only, because under Article 338, amended Article 338, there has recently been appointed a Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Under Article 338, there was a provision for 'Special Officer'; now, there is a Special Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Clause (2) of Article 338 now reads as follows, *mutatis mutandis*. This is the phrase to be used in this context, because 'Special Officer' is now replaced by 'Commission'. So it reads:

> "It shall be the duty of the Commission to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President . . . ."

This is the relevant part of the Article, which is very appropriate in this context.

[Shri H. V. Kamath]

"...upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament."

Then clause (2) of Article 339 refers to the executive power of the Central Government. It reads:

"The executive power of the Union shall extend to the giving of direction to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State."

The Minister must clarify whether this matter will be referred, besides the State Government, to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission also, and whether a report will be called for from that Commission and that report via the President will be laid on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know whether you were here earlier when the Minister replied to this specific point. He said that the matter would be referred to the Commission, but at what stage he did not know. Whether it should be referred at this stage or later, that was the point, on which he could not say anything now.

श्री विनायक प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यही तो हमारा रोना है। यही तो हमारा सवाल है कि इसे शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन को क्यों नहीं भेजा गया ?

SHRI H. M. PATEL: First of all, I will repeat again that this calling attention notice was with reference to certain incidents which took place on the 7th and 8th March.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): You kindly read it fully; you have read half of it..... (*Interruptions*).

SHRI H. M PATEL: I have said already that once it is established that this particular incident followed upon various incidents that took place earlier, we will certainly take action. I said that we did not disown responsibility in so far as the tribals are concerned; their welfare is our responsibility.

So far as this Commission is concerned, it does not have to have any reference from us before it starts any enquiry; it can enquire itself. But now that these facts have come to our notice, we will ask the State Government to clarify the position and thereafter take whatever action is called for.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I suggest that you send the entire proceedings of the House to the Commission.

SHRI H. M. PATEL: Certainly; I said that.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am shocked to hear the legalistic approach made by the hon. Minister, Shri Patel. First of all, he said that the Ministry asked for reports from the State Government and the Minister of State laid down the narration of facts. If I have understood the meaning of this English language, this statement does not contain the narration of facts. It is a tissue of lies. It does not contain narration of facts. If what the Minister said subsequently is only the narration of the report from the State Government . . .

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): The phrase "tissue of lies" is unparliamentary. You can say it is "terminological inexactitude"!

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: It is a tissue of untruth. That is what I said. If it is just an analysis of the report received from the State Government, nothing can be said. Further, the Minister is under a misconception—possibly he has corrected himself by now—while making this legal-

istic approach and quoting from the Calling Attention notice. The Calling Attention says:

"to call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported maltreatment to the representatives of the People's Union of Civil Liberties from Delhi visiting Singhbhum district on Wednesday, the 7th March, 1979 to enquire into the complaints of violation of human rights of Adivasis of Singhbhum district and widespread resentment among the people."

Now, to go into the genesis of the whole trouble, I draw your attention to this, i.e. to a statement made by an hon. Member under rule 377 as early as on 22nd December 1978.....

12.57 hrs.

(MR. SPEAKER in the Chair)

Sir, I have just begun. It is regarding the happenings against Adivasis, tortures committed against them and the SCs and STs in Chaibasa, headquarters of Singhbhum district and in the Chhota Nagpur division. What is the problem? There, the poor landless labourers were terrorized by the big landlords, who apparently had the backing of the Police, only because they were agitating for the payment of the prescribed minimum wages for farm labourers, and for a more humane treatment. They were also agitating for the replacement of sal tree plantations by teak plantations, on the ground that the seeds of the former, had food value, and were a source of subsistence for them. The team of the People's Union of Civil Liberties went to Ichahatu, Sarangda and Lonju. At Lonju, they were lathi-charged by the Police; and at Barhagora, the police had resorted to firing.

In the background of all these happenings, the team thought it necessary to go there. It moved in different areas. They met the district officers at Chaibasa on 3rd March. They met the S.P. the forest officers and also a cross-section of the people. However, the Deputy Commissioner was not available. So, they could not meet him. But the administration had information. The Minister of State for Home Affairs may kindly note this. They were beaten 4 days after this. They were beaten by the police at Barhagora. The State Government is reported to have made a statement. This is the statement before us: "There was no advance information about their visit to this area."

13 hrs.

Will the Minister take it up with the State Government, for sending a report which is not corroborated by facts? I can quota further. I have the letters. After the first happening, Shri Govinda Mukhoty frote a letter as early as on 24th December, to the Chief Minister of Bihar. In that letter, Shri Gobinda Mukhoty says:

"Recently, atrocities in Bajitpur in Bihar, where hearth and home of 169 families have been completely wiped off by 400 musclemen at the instance of a landlord, have led to lot of anxiety amongst the thinking people of this country.....

"It is inconceivable as to how miscreants went on demolishing hut after hut for eight hours, without being checkmated by the police. It is also surprising that only after 24 hours of the incident, the Superintendent of Police came to enquire about the incident. If these incidents occur, public will soon lose all confidence in the Government. As a matter of fact, if such incidents can occur in a State, the State Government ought to take responsibility and resign. But, then, we, in this country, seem to be oblivious to the sufferings of the common people."

I can quote from the letter written to the Chief Minister of Bihar.

MR. SPEAKER: Let us come to the question.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: It says:

> "This incident has so shocked the conscience of the people that over 2000 students/teachers and karamcharis of Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Institute of Economic Growth and Indian Institute of Public Administration are sending a memorandum to you."

I am not going to read the contents to save time. Then the Chief Minister of Bihar gave a reply. This was dated 21-1-1979. I shall read a small portion from the Chief Minister's letter. You can make it a part of the proceedings. Shri Karpoori Thakur says:

> "The incident of loot and assault, which took place on 15-11-1978 in the village Bajitpur, Distt Begusarai is very unfortunate/sad event. About this occurrence, cases have been registered, etc."

He also wrote about the accused persons. He said:

> "All accused persons, except seven persons, have been arrested."

I ask whether all these seven persons were the real culprits. That is why they escaped the arrest. This happens all over the country.

MR. SPEAKER: You cannot make a speech. There is a limit. After all, it is a calling attention.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: On 29th January, 1979, Gobinda Mukhoty wrote to Shri Karpoori Thakur about the coming visit of the team. Now here it is astounding that in this statement some unfortunate wrong things have been made out. The statement says that there was no advance information about the visit of the team. I am carrying the original letter of the Chief Minister with me to show that he was informed about it and there was an appointment made with he Chief Minister of Bihar at Patna on the 8th of March. If there was no beating on the 7th, they would have met the Chief Minister on the 8th at Patna and submitted their report to him. An attempt has been made through this note to show that members of the team were accompanied by naxalites. I am asking this question through you. Now the Prime Minister is also here. Suppose I am a naxalite by a political faith, is it a crime? Shall I be arrested for that? I asked this specific question whether there was any case, whether there was any arrest warrant against those so-called naxalites. They are not naxalites. One of them was engaged in Kisan samiti activities. There was no case.

MR. SPEAKER: Please come to the question.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I am dealing with the report and on the basis of it, I am putting a question. The Assistant Sub-Inspector took them to Barhagora Police Station. I heard a tape recording brought to me by the team where it was made out that one of them was known to Choudhuri Charan Singh.

हम तो इस इलाके के मालिक हैं, चरण सिंह हमारा क्या करेगा।

These types of atrocious statements were made by ordinary police officers and Assistant Sub-Inspectors of Police. Does the Minister think that merely by suspending such police officers things will be all right?

MR. SPEAKER: I have to stop recording of your speech. I am going to stop recording of your speech.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: My third question is this. Whether a comprehensive enquiry will be undertaken and whether this House will be reported about the contents of the same and the steps taken.

श्री विनायक प्रसाद यादव : वहां के पुलिस अधिकारी कहते हैं हम तो मोरारजी भाई को नहीं जानते हैं, हम तो चौधरी चरण सिंह को नहीं जानते हैं।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: The person who offered them tea was actually forced by the police to submit a complaint, under coercion, against his guests. Is it not an offence to lodge a statement which is not based on facts? What steps have been taken or proposed to be taken against such false complaint? Did the guests snatch their cups of tea offered by the host? Is it a punishable offence? One more question.

MR. SPEAKER: No further question. I am not allowing; there will be no recording. This is not a cross-examination. Only one question is allowed under the rules; I have allowed three questions.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I want to add one more thing.

MR. SPEAKER: You may want to add many more things but nothing will go on record; I am not allowing. The hon. Minister.

SHRI H. M. PATEL: I should like to refer to two points. When I say that I am placing the facts before this House, I said also, facts as reported to me by the state government. Therefore, that is clear. So far as other points are concerned, again I reported whatever was communicated by the State government. As regards other questions, question underlying this incident, I have already said that we will go into them and make a thorough enquiry; we will ask the state government to do this. To the extent tribal welfare is concerned —tribals are involved in this matter; adivasi interests are involved—we will also go into it, either directly or through a commission.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-SIXTH AND TWENTY-SEVENTH REPORTS

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): I beg to present the following Reports (English and Hindi versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (1978-79):—

(1) Twenty-sixth Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the Twentieth Report of the Committee on the Ministry of Information and Broadcasting—Reservations for, and employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in All India Radio.

(2) Twenty-seventh Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the Eleventh Report of the Committee on the Ministry of Home Affairs—Reservations for, and Employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Delhi tric Supply Undertaking.